सांध्य दैनिक 4PM

एक अच्छी तरह से बिताया दिन सुखद नींद लेकर आता है।
-लिओनार्दो दा विंची

मूल्य ₹ 3/-

जिद...सच की

www.4pm.co.in | www.facebook.com/4pmnewsnetwork | @Editor_SanjayS | YouTube @4pm NEWS NETWORK

● वर्ष: 12 ● अंक 134 पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, शनिवार 20 जून, 2026

दो हार के बाद न्यूजीलैंड ने खोला जीत... 7
होर्मुज का ताला खुला, दुनिया... 3
राम मंदिर दान चोरी की जांच... 2

सरकार की परीक्षा छात्रों का एग्जाम

» नीट यूजी-26 परीक्षा को सकुशल समपन्न कराने का सरकार पर दबाव

» चप्पे-चप्पे पर पहरा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। नीट यूजी -26 परीक्षा को सकुशल समपन्न कराने के लिए सरकार की तरफ से अभूतपूर्व व्यवस्था किये जाने के दावे किये जा रहे हैं।

एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने देशभर में बनाये गये पांच हजार परीक्षा केन्द्रों को हैंडओवर कर लिया है और आज सभी सेंटर्स पर माकड्रिल का आयोजन किया गया। परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली या गड़बड़ी को रोकने के लिए इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए। टेलीग्राम बंद कर दिया गया है। गाड़ियों में जीपीएस के साथ ही पैरामिलिट्री का पहरा भी है।

थ्री लेयर सिक्योरिटी

एग्जाम सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरों का सीधा एक्सेस एनटीए के पास रहेगा। इस बार नीट परीक्षा को लेकर तीन लेयर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाओं को लाने ले जाने और सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी पैरामिलिट्री फोर्स को सौंपी गई है। पेपर ले जाने वाली गाड़ियों को जीपीएस ट्रेकिंग होगी। अफवाहों और पेपर लीक के दावों को रोकने के लिए एक हाईलेवल मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया है। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है। टेलीग्राम को 22 जून तक अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही देश की तमाम जांच एजेंसियां जिला प्रशासन और केंद्र व राज्य सरकारों के बड़े अधिकारी भी इस पूरी परीक्षा पर सीधा कंट्रोल रखेंगे।

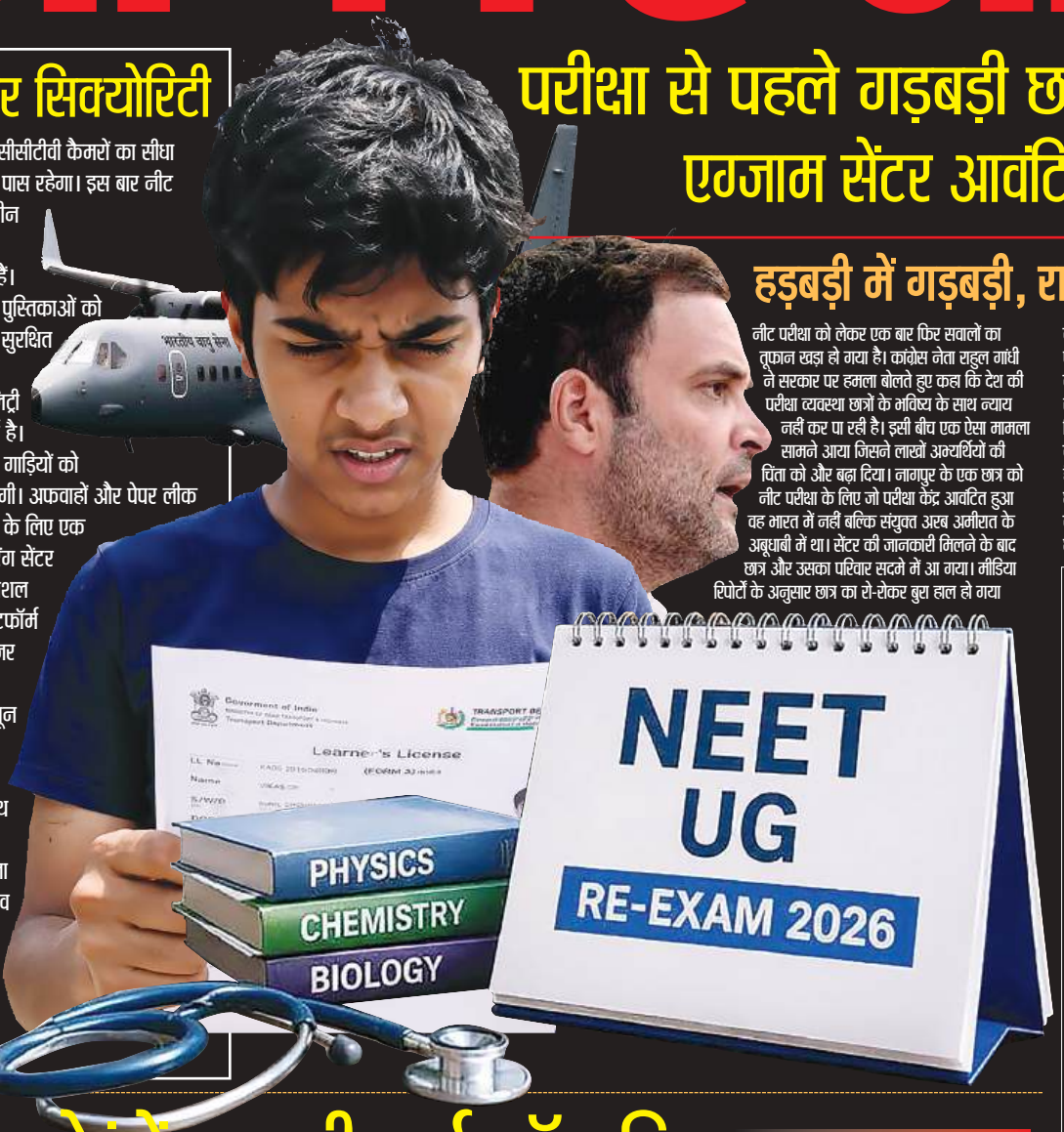

परीक्षा से पहले गड़बड़ी छात्र को अबूधाबी एग्जाम सेंटर आवंटित कर दिया गया

हड़बड़ी में गड़बड़ी, राहुल गांधी का आरोप

नीट परीक्षा को लेकर एक बार फिर सवालों का तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की परीक्षा व्यवस्था छात्रों के भविष्य के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसने लाखों अभ्यर्थियों की चिंता को और बढ़ा दिया। नागपुर के एक छात्र को नीट परीक्षा के लिए जो परीक्षा केंद्र आवंटित हुआ वह भारत में नहीं बल्कि संयुक्त अरब अमीरात के अबूधाबी में था। सेंटर की जानकारी मिलने के बाद छात्र और उसका परिवार सदमे में आ गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार छात्र का रो-रोकर बुरा हाल हो गया क्योंकि उसके लिए इतनी कम अवधि में विदेश जाकर परीक्षा देना लगभग असंभव था। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को उठाते हुए कहा कि जब परीक्षा प्रणाली ही भरोसेमंद नहीं रहेगी तो छात्रों का मनोबल कैसे बचेगा। उनका आरोप है कि सरकार युवाओं की सबसे बड़ी चिंता शिक्षा और रोजगार को गंभीरता से नहीं ले रही है। नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं है यह लाखों परिवारों के सपनों का दरवाजा है। ऐसे में एक छोटी सी प्रशासनिक चूक भी किसी छात्र के लिए पूरे साल की मेहनत पर भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि अब छात्र सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि जवाबदेही भी मांग रहे हैं।

सामने आयी गड़बड़ी

पिता बोले- अबू धाबी में सेंटर आवंटित होने से सदमे में है बेटा

नीट यूजी 26 की दोबारा परीक्षा से पहले एक बड़ी प्रशासनिक चूक सामने आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा जारी एडमिट कार्ड में हुई एक गलती के कारण महाराष्ट्र के नागपुर के एक छात्र को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया गया। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले हुई इस घटना ने छात्र और उसके माता पिता को अंदर तक हिला कर रख दिया। छात्र के परिवार के अनुसार अब्दुल्ला ने आवेदन करते समय नागपुर, वर्धा और भंडारा को परीक्षा के लिए अपनी पसंद के शहरों के तौर पर चुना था। लेकिन उसके एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र अबू धाबी यूएई में दिखाया गया। नीट अभ्यर्थी अब्दुल्ला के पिता मोहम्मद

तालिब ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हम विदेश में परीक्षा केंद्र मिलने पर हैरानी और उलझन जाहिर में हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ। अब सिर्फ एजेंसी ही इसका कारण बता सकती है। हमने परीक्षा के लिए अपनी पसंद के तीन केंद्र चुने थे लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह हमें अबू धाबी क्यों भेजना चाहते हैं। तालिब ने बताया कि उनके बेटे अब्दुल्ला ने पहले नीट परीक्षा दी थी और उन्हें नागपुर में सेंटर मिला था। परीक्षा ठीक से हुई और एप्लीकेशन प्रोसेस या परीक्षा सेंटर चुनने में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तालिब ने कहा पिछली नीट परीक्षा में उन्हें नागपुर में ही सेंटर मिला था। बेटे का पेपर बहुत अच्छा गया था। सेंटर चुनने में हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई थी।

परीक्षा केंद्रों पर की गई मॉकड्रिल

नीट-यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा से पहले आज दिल्ली समेत देश भर के परीक्षा केंद्रों पर मॉकड्रिल की गई। इस दौरान परीक्षा केंद्रों की निगरानी समेत अन्य पहलुओं को पुलिस सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने देखा। नोएडा में भी नीट की दोबारा परीक्षा से पहले सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के लिए सेक्टर 46 के भवानी शंकर इंटर कॉलेज में मॉक ड्रिल की गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर 21 जून को होने वाली परीक्षा से पहले शहर भर के नीट परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें 25 केंद्रों पर 9050 उम्मीदवार कड़ी एंट्री और टाइमिंग नियमों के तहत परीक्षा में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि प्रयागराज में 47 केंद्रों पर नीट यूजी आयोजित की जाएगी और सभी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। कल सुबह एक मॉक ड्रिल और ड्राई रन किया जाएगा। हमने यह सुनिश्चित

किया है कि छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर कोई असुविधा न हो। उत्तर प्रदेश के वाराणसी रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने कहा कि नीट परीक्षा के लिए हमें लगभग 25,000 उम्मीदवारों की सूची मिली है जो यहां आएंगे। उनके लिए जगह की व्यवस्था करने और स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम अपने आरपीएफ और जीआरपी स्टाफ के साथ अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल टीम को भी स्टेशन पर मौजूद रहने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। नीट री-एग्जाम पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। सरकार जो कोशिशें कर रही है हम उसकी सराहना करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। जिस तरह से सरकार काम कर रही है मुझे नहीं लगता कि ऐसी घटनाएं दोबारा होंगी। गुजरात के राजकोट स्थित धर्मेंद्र सिंह कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल शिशिर भारद्वाज ने कहा कि इस कॉलेज में कुल 552 छात्र-छात्राओं को अलॉट किया गया है। यह नीट का री-एग्जाम है जो बहुत संवेदनशील मामला है। हम सरकार के सभी निर्देशों का सख्ती से पालन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल स्थित खड़गपुर केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल और नीट डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज संग्राम बनर्जी ने कहा है कि पेपरलीक की वजह से नीट का एग्जाम दूसरी बार हो रहा है। हमारे जिले में लगभग 13 केंद्र हैं और करीब 6500 छात्र री-टेस्ट दे रहे हैं। हरियाणा में नीट री-एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए दो दिन तक मुफ्त बस यात्रा की व्यवस्था की गई है। छात्र अपना एडमिट कार्ड दिखाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। करनाल बस स्टैंड के इंचार्ज सोनू ने कहा सरकार ने 20 और 21 जून के लिए एडवाइजरी जारी की है। नीट एग्जाम देने वाले छात्र अपना एडमिट कार्ड दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। दिल्ली में एक छात्र ने कहा कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। मैं पिछले सालों के प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहा हूं। पिछली बार परीक्षा रद्द हो गई थी और मैं बहुत निराश हुआ था। इस बार भी मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं ताकि सफल हो सकूं।

राम मंदिर दान चोरी की जांच पर रोजाना हो ब्रीफिंग : अखिलेश यादव

» बोले सपा प्रमुख, भाजपा का सूपड़ा हो जाएगा साफ

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। राम मंदिर चढ़ावा मामला अभी शांत होने वाला नहीं है। सपा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एकबार फिर इसको लेकर भाजपा व सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा मुखिया ने कहा कि चंदा चोरी की जांच कहां तक पहुंची, इसकी नियमित ब्रीफिंग होनी चाहिए। मथुरा से भी आई धांधली की खबर बेहद गंभीर है, उसकी भी उच्चस्तरीय विश्वसनीय जांच हो।

उन्होंने जारी बयान में कहा कि अयोध्या महापापियों के लिए कुरुक्षेत्र साबित होगी। यहीं भाजपा की राजनीति का आरंभ हुआ था और यहीं अंत भी होगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में चढ़ावे-चंदे-दान-शिला चोरी की घटना के बाद से यहां आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या पर नकारात्मक असर पड़ा है। लोगों की आस्थाएं खंडित हुई हैं। इसका सीधा असर अयोध्या के स्थानीय कारोबार और आम आदमी की आमदनी पर पड़ा है। सरकार की गलती का खामियाजा जनता क्यों भुगते।

उन्होंने कहा कि अयोध्या और आसपास के सभी क्षेत्रों में भयंकर आक्रोश पनप रहा है। जिन भाजपा नेताओं और उनके संगी-साथियों की वजह से कलुषित हुई है, वो अपना कारनामा करके सदैव की तरह भूमिगत हो गए हैं। अस्पष्टता के कारण वातावरण और भी शंकापूर्ण व तनावपूर्ण हो गया है। स्थानीय लोग मंदिर जाने से भी घबरा रहे हैं कि कहीं उनको ही जांच के नाम पर फंसा न दिया जाए। जांच कहां तक पहुंची, इसकी रोजाना ब्रीफिंग होनी चाहिए। भाजपा सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार के कारण जनता का अब एसआईटी पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है।

दूध का दूध नहीं, सोने का सोना करें

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि उनके भाषण में बयान कम, धमकी अधिक थी। सूत्र बता रहे हैं कि स्थानीय भाजपा विधायकों और पदाधिकारियों के कहने पर ये कार्यक्रम अचानक तय किया गया, जिससे कि भाजपा की राजनीति ज़मीन बचाई जा सके। अन्यथा, अयोध्या मंडल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा का सूपड़ा साफ होना तय है। अखिलेश ने कहा कि भौतिक रूप से भ्रमण कर उस एसआईटी के काम को प्रभावित करने की कोशिश न की जाए, जो पहले से ही विवादास्पद सदस्यों के कारण शंकाओं के घेरे में है। जनता कह रही है कि दूध का दूध, पानी का पानी नहीं, बल्कि सोने का सोना, चांदी का चांदी करें। चढ़ाए गए पैसों, अनमोल शिलाओं के अलावा बहुमूल्य धातुओं और जेवरों का भी हिसाब देना ही पड़ेगा।

एकबार फिर राजभर ने सपा प्रमुख पर साधा निशाना

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। ओपी राजभर ने अपने एक्स अकाउंट से अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने लिखा- अखिलेश बाबू छुप-छुप के मुंबई क्यों जा रहे हो? अरे वहां तो केवल दो ही विधायक हैं, वो टूट जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां वाले जो भागने की तैयारी में हैं, उन्हें कौन देखेगा? मानसून सत्र शुरू होने से पहले अपने सांसदों को कर्नाटक के जिस रिसॉर्ट में ले जाना चाहते हैं, वो हो नहीं पाएगा।

क्योंकि मैंने जो कहा है न कि सपा में गड़बड़ चल रहा है, ये स्क्रीन शॉट उसका एक नमूनाभर है। बात इससे आगे जा चुकी है। अरे वहां तो केवल दो ही विधायक हैं, वो टूट जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां वाले जो भागने की तैयारी में हैं, उन्हें कौन देखेगा? मानसून सत्र शुरू होने से पहले अपने सांसदों को कर्नाटक के जिस रिसॉर्ट में ले जाना चाहते हैं, । सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का तीखा हमला बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। उन्होंने अपने अधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए सपा अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए सपा सांसदों के टूटने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बिना किसी नाम लिए लिखा है कि सपा सांसदों के टूटने वाले गुट का नेतृत्व बागी बलिया की धरती से ताल्लुक रखने वाले एक सांसद करेंगे। राजभर ने इशारा किया है कि सपा कार्यालय में आयोजित सम्मेलन में ब्राम्हणों का जिस तरह से तिरस्कार किया गया है, उससे बागी बलिया का लाल बहुत आहत है। इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया है। राजभर ने लिखा है कि मेरी एक प्रतिक्रिया पर जिस तरह से पूरा सैफई खानदान मुझे गाली देने और सफाई देने में जुट गया, उससे ज्यादा बेहतर है कि अखिलेश ट्विटर, एसी और पीसी वाली नेतागिरी छोड़कर अब सांसद बचाओ अभियान शुरू कर दें और दुखी एवं निराश सांसदों के घर जाकर उनसे माफी मांगें।

राहुल गांधी को परशुराम दिखाने पर सियासी घमासान

» भाजपा ने कहा हिंदुओं का किया अपमान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

वाराणसी। राहुल गांधी के जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस वाराणसी द्वारा उन्हें भगवान परशुराम के रूप में दर्शाने वाले पोस्टर को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इस चित्रण को हिंदुओं और सनातन धर्म का अपमान बताते हुए कांग्रेस की आलोचना की, जबकि कांग्रेस ने इसे अपने नेता के प्रति कार्यकर्ताओं की भावनाएं बताया। यह घटना राहुल गांधी के जन्मदिन समारोह के दौरान हुई, जिसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है।

यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गंगा किनारे पूजा की और राहुल गांधी का एक पोस्टर लेकर आए, जिसमें उन्हें भगवान परशुराम के रूप में दिखाया गया था। पोस्टर में नेता को एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में भारत के संविधान की एक प्रति पकड़े हुए दिखाया गया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर पर दूध चढ़ाया और वैदिक मंत्रों के साथ रुद्राभिषेक किया। उन्होंने 11 किलो का लड्डू केक भी काटा और राहुल गांधी के लंबे, स्वस्थ और सफल जीवन के लिए प्रार्थना की। लेकिन राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दिखाने से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया और बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पार्टी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस काम को अस्वीकार्य और भगवान परशुराम का अपमान बताया। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की बुद्धि मारी गई है। भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के अवतार हैं। राहुल गांधी की तुलना भगवान परशुराम से करना बिल्कुल असंभव और समझ से परे है। जो लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं, वे खुद की तुलना भगवान परशुराम से करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भगवान परशुराम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता 364 दिन सनातन धर्म का अपमान करते हैं और एक दिन भगवान परशुराम को याद करने का दिखावा करते हैं।

लालू सिर्फ सियासत कर रहे : चौधरी

» पूर्व सीएम की सुरक्षा दावों को जदयू ने नकारा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। जदयू ने लालू प्रसाद यादव के इस आरोप को सिरे से खारिज किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी और राबड़ी देवी की सुरक्षा कम करने तथा सरकारी आवास खाली कराने के पीछे हैं। पार्टी ने इसे लालू की दबाव की राजनीति बताते हुए स्पष्ट किया कि सुरक्षा और आवास संबंधी फैसले सरकारी समितियों द्वारा स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं, जिनमें कोई राजनीतिक दखल नहीं होता।

जदयू ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद के उस आरोप को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को दी गई सुरक्षा कम करने के बिहार सरकार के फैसले के पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ था। लालू की बातों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जब तक नीतीश कुमार सत्ता में थे, वे राबड़ी देवी के घर पर रहे। अब जब सरकार ने उन्हें अलग और सही घर दिया है, तब भी वे दबाव की राजनीति कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि नीतीश ही यह सब करवा रहे हैं। सुरक्षा और घर से जुड़े फैसलों में राजनीतिक दखल के आरोपों को खारिज करते हुए चौधरी ने कहा कि सुरक्षा समिति और पुलिस विभाग ऐसे फैसले स्वतंत्र रूप से लेते हैं। बुधवार को लालू ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार पर आरोप लगाया था कि उनकी सुरक्षा कम करने के बिहार सरकार के फैसले के लिए वही जिम्मेदार हैं। हाल ही में, एनडीए सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू और राबड़ी देवी की जेड-प्लस सुरक्षा कम कर दी थी और उन्हें 10, सर्कुलर रोड स्थित सरकारी घर खाली करने का निर्देश दिया था। एक और मंत्री, मदान साहनी ने कहा कि लालू लगभग 20 साल तक उस घर में रहे और उस दौरान किसी ने भी उनसे घर खाली करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अब जब सरकार बदल गई है, तो यह मामला भवन निर्माण विभाग और सुरक्षा समिति के अधिकार क्षेत्र में आता है। लालू जी को इस मामले में नीतीश का नाम नहीं लेना चाहिए था। बिहार पुलिस ने यह भी साफ़ किया कि तय नियमों के अनुसार लालू और राबड़ी देवी दोनों को पर्याप्त सुरक्षा दी जा रही है। बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में पुलिस ने कहा कि दोनों नेताओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था तय प्रावधानों के अनुसार बनाए रखी जा रही है।

बामुलाहिजा

कार्टून: हसन जैदी

प्रधान के सत्ता में रहने से बच्चों का भविष्य असुरक्षित : वडेट्टीवार

» नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस नेता ने शिक्षामंत्री को घेरा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। कांग्रेस विधायक विजय नामदेवराव वडेट्टीवार ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों के सत्ता में रहते हुए बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। उन्होंने मांग की कि प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से हटाया जाए। वडेट्टीवार ने यहां पत्रकारों से कहा, धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि वे इसके लायक नहीं हैं। अगर सरकार में थोड़ी भी जवाबदेही की भावना है, तो उसे गड़बड़ियों को ठीक करना चाहिए। ऐसे लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जब तक धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग सत्ता में रहेंगे, तब तक बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं माना जा सकता।

उनके ये बयान शिक्षा से जुड़ी नीतियों और परीक्षा प्रणालियों को लेकर विपक्ष और केंद्र के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच आए हैं। इस बीच, नागपुर के एक नीट उम्मीदवार को परीक्षा के लिए पसंदीदा शहर के तौर पर नागपुर चुनने के बावजूद अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया गया। यह घटनाक्रम 21 जून को होने वाली मेडिकल प्रवेश परीक्षा से ठीक एक दिन पहले सामने आया, जिससे उम्मीदवार और उसका परिवार अनिश्चितता की स्थिति में आ गए। बाद में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने शनिवार को स्पष्ट किया कि नीट की दोबारा परीक्षा के लिए नागपुर के एक छात्र को अबू धाबी में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाने का मामला सुलझा लिया गया है। एएनआई से बात करते हुए, एनटीए के छत्र अभिषेक सिंह ने बताया कि गड़बड़ी को ठीक कर दिया गया है और छात्र को उनके गृह नगर में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है। सिंह ने ,हड्ड को बताया, मामला सुलझा लिया गया है और उम्मीदवार को अब नागपुर में परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नागपुर के एक नीट उम्मीदवार के बारे में एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एनटीए द्वारा आयोजित पुन: परीक्षा के लिए छात्र को कथित तौर पर अबू धाबी में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाने के बाद उसे भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

होर्मुज का ताला खुला, दुनिया ने ली राहत की सांस

लेकिन क्या भारत ने खो दिया पश्चिम एशिया का अपना पुराना रुतबा?

युद्ध खत्म होने के बाद चर्चा मिसाइलों की नहीं बल्कि कूटनीति की हो रही है

» आग का दरिया, तेल की राजनीति और भारत की खामोशी पर उठते सवाल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। 14 प्वाइंट समझौते पत्र पर डिजिटल सिग्नेचर होने के बाद मध्य पूर्व में शांति की आहट सुनाई देना शुरू हो गयी है। ईरान–अमेरिका समझौते का एलान होने के बाद होर्मुज को खोल दिया गया है और एक दो दिनों के भीतर जहाजों की आवाजाही शुरू हो सकती है। ईरान–इजरायल–अमेरिका युद्ध एक आग का दरिया था और समझौते के लिए इन देशों को तैर के जाना जैसा था। समझौते से पहले कामोवेश ईरान और अमेरिका की कुछ ऐसी ही स्थिति थी। जंग बंद होने के बाद हालात तेजी से सामान्य होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

इस जंग में कौन जीता कौन हारा इस बात का आंकलन करे तो जो प्वाइंटस सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक जंग में ईरान की जीत हुई और पाकिस्तान की कूटनीति की तारीफ हो रही है। भारत की खमोशी पर सवाल है और पूरी दुनिया चीख कर कह रही है अमेरिका ने घुटने टेक दिये हैं। जिस होर्मुज को खोलना ही सबकुछ माना जा रहा है वह होर्मुज तो जंग से पहले खुला ही था और जहाज उस रास्ते से बे रोकटोक आ जा रहे थे। जंग शुरू होने से कुछ दिन पहले पीएम मोदी के इजरायल दौरे का खमियाजा कुछ हद तक भारत को भी भुगतना पड़ा। ईरान की तरफ से आये शुरूआती संदेशों को देखे तो ईरान ने हमेशा यह चाहा कि भारत मध्यस्थ की भूमिका निभाए लेकिन भारतीय कूटनीति के स्पष्ट होने के बाद ईरान ने भारत की ओर देखना बंद कर दिया। बाहरहाल गैस और तेल की किल्लत ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और डबल डिजिट इन्फलेशन की ओर धकेल दिया।

इस पूरी कहानी में भारत कहां था?

एक समय था जब पश्चिम एशिया में भारत को भरोसेमंद संतुलित और संवाद स्थापित करने वाली शक्ति माना जाता था। ईरान से भारत के ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। खाड़ी देशों से भारत की आर्थिक जीवनरेखा जुड़ी हुई है। इजरायल भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सहयोगी बनता जा रहा है। ऐसे में जब पश्चिम एशिया धधक रहा था तो उम्मीद थी कि नई दिल्ली किसी निर्णायक मध्यस्थ किसी शांतिदूत या कम से कम किसी प्रभावशाली संवादकर्ता की भूमिका में दिखाई देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने सावधानी बरती संतुलन साधा और किसी भी पक्ष में खुलकर खड़े होने से परहेज किया। यह नीति कूटनीतिक दृष्टि से सुरक्षित जरूर रही लेकिन इससे वह राजनीतिक स्पेस भी खाली रह गया जिसे भरने की कोशिश पाकिस्तान और कुछ अन्य क्षेत्रीय ताकतों ने की। दिलचस्प बात यह है कि युद्ध खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा मिसाइलों की नहीं बल्कि कूटनीति की हो रही है। कौन जीता? कौन हारा? क्या अमेरिका अपने सभी रणनीतिक लक्ष्य हासिल कर पाया? क्या ईरान दबाव के बावजूद झुका? क्या इजरायल अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम प्राप्त कर सका? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल–क्या भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में एक अवसर खो दिया? यह वह सवाल है जो शांति स्थापित होने के बाद हवा में तैर रहे हैं। युद्ध के दौरान तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर जो आशंकाएं पैदा हुईं उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोर नसों को उजागर कर दिया। आयातित ऊर्जा पर निर्भरता ने एक बार फिर याद दिलाया कि पश्चिम एशिया में उठने वाला हर तूफान अंततः भारतीय बाजारों तक पहुंचता है। पेट्रोल-डीजल से लेकर खाद्य पदार्थों और परिवहन तक हर क्षेत्र पर इसका असर दिखाई देता है। अब जबकि समझौते की राह खुलती दिखाई दे रही है दुनिया राहत महसूस कर रही है। लेकिन यह राहत स्थायी होगी या नहीं इसका जवाब आने वाले कुछ महीनों में मिलेगा। क्योंकि पश्चिम एशिया में युद्ध खत्म होने से ज्यादा मुश्किल काम होता है शांति को बनाए रखना। और यही वह जगह है जहां भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है। क्या वह सिर्फ दर्शक बना रहेगा या फिर आने वाले दौर में अपनी ऐतिहासिक कूटनीतिक भूमिका को दोबारा हासिल करेगा?

14 प्वाइंट समझौता

अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित 14-पॉइंट समझौते के तहत दोनों देशों ने सबसे पहले सभी सैन्य कार्रवाइयों और प्रत्यक्ष लड़ाई को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त करने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में जारी संघर्ष और तनाव को रोकने का भी प्रावधान रखा गया है। समझौते के अनुसार दोनों पक्ष 60 दिनों के भीतर एक व्यापक और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए वार्ता पूरी करेंगे जबकि आपसी सहमति होने पर इस वार्ता अवधि को आगे बढ़ाने की अनुमति भी होगी। समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ा है। इसके तहत होर्मुज जलमार्ग को तुरंत खोलने, ईरान द्वारा सभी वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने तथा शुरुआती 60 दिनों तक जहाजों के लिए होर्मुज से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आवागमन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। दूसरी ओर अमेरिका भी ईरान के खिलाफ लागू नौसैनिक नाकेबंदी को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। आर्थिक मोर्चे पर समझौते में अमेरिकी प्रतिबंधों को धीरे-धीरे समाप्त करने, ईरान की जब्त विदेशी संपत्तियों को क्रमिक रूप से जारी करने तथा ईरानी तेल निर्यात को सुचारु बनाने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी वेवर (विशेष वित्तीय अनुमति) देने की बात कही गई है। इसके अलावा ईरान के आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास के लिए अमेरिका समर्थित लगभग 30 अरब डॉलर के आर्थिक एवं पुनर्निर्माण कार्यक्रम का भी उल्लेख किया गया है। परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर ईरान ने दोहराया है कि वह परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। वहीं अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार और उससे जुड़े भविष्य के प्रबंधों पर आगे बातचीत जारी रखने का प्रस्ताव रखा गया है। कुल मिलाकर यह 14-सूत्रीय समझौता सैन्य तनाव कम करने, क्षेत्रीय स्थिरता बहाल करने, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित बनाने और ईरान-अमेरिका संबंधों को एक नई दिशा देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

ईरान का सैन्य शक्ति के साथ राजनीतिक जीत का दावा

युद्ध का मूल्यांकन केवल बमों और मिसाइलों से नहीं होता। ईरानी मीडिया का तर्क है कि उसने भारी दबाव प्रतिबंधों और सैन्य चुनौतियों के बावजूद अपने राजनीतिक अस्तित्व और क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखा। तेहरान जंग में खुद की जीत के तौर पर प्रस्तुत कर रहा है। हालांकि ईरान के भीतर एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि समझौता उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। इसलिए वहां असंतोष और बहस दोनों दिखाई दे रहे हैं।

पाकिस्तान की कूटनीति की चर्चा

इस पूरे संकट के दौरान पाकिस्तान ने खुद को संवाद और संतुलन की राजनीति के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश की। इससे उसे कुछ मंचों पर चर्चा और कूटनीतिक दृश्यता अवश्य मिली। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि इससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में कोई बड़ा बदलाव आ गया है। फिर भी यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि जहां भारत को संभावित मध्यस्थ के रूप में देखा जा रहा था वहां चर्चा का एक हिस्सा पाकिस्तान की सक्रियता पर केंद्रित हो गया।

होर्मुज खुला तो दुनिया बची

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज विश्व ऊर्जा आपूर्ति की सबसे महत्वपूर्ण धमनियों में से एक है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और एलएनजी इसी मार्ग से गुजरता है। युद्ध के दौरान सबसे बड़ा डर यह था कि यदि यह समुद्री रास्ता बाधित हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। इसका सबसे बड़ा असर उन देशों पर पड़ता जिनकी ऊर्जा जरूरतें आयात पर आधारित हैं। भारत उनमें प्रमुख है। युद्ध विराम और समुद्री गतिविधियों के सामान्य होने से तत्काल आर्थिक राहत मिली है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में घबराहट कम हुई है और ऊर्जा आपूर्ति पर मंडरा रहा संकट कुछ हद तक टलता दिखाई दे रहा है।

इजरायल क्यों खुश नहीं दिख रहा?

इजरायल की रणनीति हमेशा सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता के इर्द-गिर्द घूमती है। यदि किसी समझौते से उसके सभी सुरक्षा उद्देश्य पूरे नहीं होते तो वहां असंतोष स्वाभाविक माना जाता है। यही वजह है कि समझौते को लेकर इजरायल के भीतर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तेल अवीव की चिंता यह है कि क्या यह समझौता स्थायी शांति लाएगा या केवल अगले संघर्ष तक का विराम साबित होगा।

भारत के लिए सबसे बड़ा सबक

यह पूरा संकट भारत को तीन महत्वपूर्ण सबक देता है। पहला ऊर्जा सुरक्षा को केवल बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरा पश्चिम एशिया में संतुलित संबंध बनाए रखना पर्याप्त नहीं है प्रभावशाली भूमिका भी जरूरी है। तीसरा भविष्य की वैश्विक राजनीति में केवल आर्थिक शक्ति नहीं बल्कि संकट प्रबंधन की क्षमता भी नेतृत्व तय करेगी। क्योंकि युद्ध अभी रुका है इतिहास नहीं सभी जानते हैं कि पश्चिम एशिया में बंदूकें कुछ समय के लिए शांत हो सकती हैं लेकिन भू-राजनीति कभी नहीं सोती। आज होर्मुज खुला है जहाज चल रहे हैं तेल उपलब्ध है और बाजार राहत महसूस कर रहे हैं लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है। अगले दो महीने तय करेंगे कि यह वास्तविक शांति है या अगली लड़ाई से पहले का विराम। भारत के सामने भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा है। क्या वह केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाला देश बना रहेगा? या फिर वह उस भूमिका में लौटेगा जहां दुनिया संकट के समय उसकी ओर समाधान खोजने के लिए देखती थी? क्योंकि पश्चिम एशिया का इतिहास बताता है कि वहां युद्ध अचानक शुरू होते हैं लेकिन उनका प्रभाव हजारों किलोमीटर दूर बैठी अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंचता है। और भारत उन अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे खड़ा है।

जिद... सच की

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

संवैधानिक संस्थाओं पर चोट मतलब लोकतंत्र पर आंच

आजादी के बाद देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि संवैधानिक संस्थाओं को पक्षपात के आरोपों के कारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इन संस्थाओं के कामकाज के तौर–तरीकों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन पर पूरी तरह से सत्तारुढ केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के इशारों पर काम करने करने और विपक्ष के अधिकारों को दबाने के आरोप लगाए जा रहे हैं।

आजकल देश में सरकार के कई कामों पर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल केवल विपक्ष ही नहीं आम जनता की ओर से भी उठाए जा रहे हैं। अब ये चर्चा खास व जनता में आम हो गई है देश में समय के साथ लोकतंत्र के परिपक्व होने के बजाए कमजोर होने की आहट आ रही है। आजादी के बाद देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि संवैधानिक संस्थाओं को पक्षपात के आरोपों के कारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इन संस्थाओं के कामकाज के तौर–तरीकों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन पर पूरी तरह से सत्तारुढ केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के इशारों पर काम करने करने और विपक्ष के अधिकारों को दबाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोपों के इस घेरे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति रहे जगदीप धनखड़, भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक और अब मुख्य चुनाव आयुक्त आ चुके हैं। लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए 118 विपक्षी सांसदों के समर्थन से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। विपक्षी सांसदों का दावा था कि ओम बिरला ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार दिखाया है और उनका कार्यालय अपेक्षित निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रहा है।

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कई बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्पीकर की भूमिका पर चर्चा हुई है और कई बार मेरा नाम लिया गया, मेरे बारे में गंदी बातें कही गईं। उन्होंने कहा कि यह सदन भारत के लोगों की अभिव्यक्ति है। यह सदन किसी एक पार्टी का नहीं है, यह पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। जब भी हम बोलने के लिए उठते हैं, हमें बोलने से रोक दिया जाता है। पिछली बार जब मैंने बात की थी, तब मैंने हमारे प्रधानमंत्री के किए गए समझौतों के बारे में एक बुनियादी सवाल उठाया था। कई बार मुझे बोलने से रोका गया है। पहली बार लोकसभा के इतिहास में नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 17वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 51प्रतिशत थी। नेशनल एवरेज 66प्रतिशत था। 16वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 52प्रतिशत थी। नेशनल एवरेज 80 प्रतिशत था। 15वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 43प्रतिशत थी, जबकि नेशनल एवरेज 76प्रतिशत था। उन्होंने कुछ सदस्यों की शिकायतों पर भी बात की कि उन्हें माइक्रोफोन की दिक्कतों की वजह से बोलने नहीं दिया गया। शाह ने कहा कि जो कोई भी नियमों का पालन नहीं करेगा या सदन में अनुशासन बनाए नहीं रखेगा, उसका माइक्रोफोन बंद कर दिया जाएगा और कहा कि संसद की कार्यवाही इसी तरह चलनी चाहिए। तो अब आम जनता भी पूछ रही है कि क्या दबंगई से सरकार संसद को चलाएगी ।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

अब फिर रूस पर शिकंजा कसने की तैयारी

पुष्परंजन

जी–7 (ग्रुप ऑफ सेवन) नेताओं का शिखर सम्मेलन आखिकार समाप्त हो गया। जी–7 के मंच पर उभयपक्षीय बातचीत के दौरान मोदी ने ट्रंप से कहा, 'भारतीय नाविकों की सुरक्षा जरूरी है।' मोदी ने यह भी कहा, कि उन्हें खुशी है भारतीय और अमेरिकी टीमें लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। मोदी ने 'अमेरिका के साथ संबंधों में नई गति और ऊर्जा' पर जोर दिया। फ्रेंच आल्प्स के एवियन–लेस–बेन्स में होटल रॉयल में, जहां जी–7 समिट के लिए जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, यूके और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बार–बार सभी से कहा कि ईरान के साथ उनकी 'डील' 'जबरदस्त' थी। दुनिया की सात सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। जी–7 में यूरोपीय संघ का भी प्रतिनिधित्व है।

बुधवार सुबह जारी एक बयान में, जी–7 के नेताओं ने रूसी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाने का संकल्प लिया। नेताओं के बयान में कहा गया, 'इस नई गति को समर्थन देने और तेज करने के लिए, हम एयर डिफेंस क्षमताएं, इंटरसेप्टर तथा लंबी दूरी की युद्धक क्षमताएं उपलब्ध कराने को बढ़ाने पर सहमत हैं। हम अपने प्रतिबंधों को और मजबूत करेंगे, जिसमें तेल और गैस सेक्टर पर लगाए गए प्रतिबंध भी शामिल हैं।' यह बयान उस सकारात्मक माहौल को दर्शाता है जो मंगलवार को तब बना था जब जी–7 नेताओं ने अपने पहले आधिकारिक एजेंडे की शुरुआत करते हुए बैठक में सबसे पहले यूक्रेन पर चर्चा की थी। इस साल की बैठक के मेजबान इमैनुएल मैक्रों ने शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के तौर पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को आमंत्रित करके यह स्पष्ट कर दिया था कि यूक्रेन जी–7 के एजेंडे में सबसे ऊपर है। पिछले कुछ महीनों में ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ चल रहे तनाव में उलझा हुआ था। लेकिन उससे पहले ही, उनके प्रशासन ने यूक्रेन की मदद करने की जिम्मेदारी यूरोपीय सहयोगियों पर छोड़ दी थी, और ईयू ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है।

27 सदस्यीय ईयू यूक्रेन को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद देने वाला संगठन बन चुका है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान युद्ध के दौरान तेल की कीमतें कम करने के लिए रूस पर जो प्रतिबंध हटाए गए थे, उन्हें फिर से लागू किया जा सकता है, क्योंकि अब होर्मुज

जलडमरूमध्य से ज्यादा तेल की आवाजाही हो रही है। ट्रंप ने यह भी कहा कि 'रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध खत्म करने के लिए समझौता करना चाहिए' और साथ ही कहा कि वह 'जो कुछ भी कर सकते हैं, करेंगे।' यह उन यूरोपीय नेताओं के लिए अच्छी खबर थी जो यूक्रेन को समर्थन देने से जुड़े सवालों का सामना करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। अमेरिकी प्रेस में लीक हुई कुछ जानकारियों से पता चलता है कि अमेरिका ईरानी तेल पर लगी पाबंदियां हटाने के लिए तैयार हो सकता है, जिससे ईरान को अपने फंड फिर से भरने का मौका मिलेगा। इसके बदले में ईरान को बस यह वादा करना होगा कि वह कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान का मुद्दा जल्द ही 'पीछे छूट जाएगा', लेकिन अभी के लिए वह 'ईरान पर ध्यान केंद्रित' किए हुए हैं। जानकारों का कहना है कि रूस अब थकने लगा है। यूक्रेन की ड्रोन युद्ध क्षमता जैसे कि लंबी दूरी के ड्रोन लॉन्च करने की उसकी काबिलियत, जिसका इस्तेमाल उसने इस महीने की शुरुआत में सेंट पीटर्सबर्ग में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने के लिए किया था– एक बड़ी वजह है जिसने उसे रूस द्वारा हासिल की गई बढ़त को पलटने में मदद की है। हालांकि, समिट से ठीक पहले, ट्रंप ने मीडिया और सोशल नेटवर्क दोनों पर जी–7 नेताओं की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की हिम्मत पर सवाल उठाए और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को सार्वजनिक रूप से सलाह दी कि वे अमेरिका की आलोचना करने के बजाय 'अपने बिखरते हुए देश पर ध्यान दें'। उन्होंने यह भी धमकी दी थी कि अगर पेरिस, गूगल, एप्पल और अमेजन जैसी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर अपना डिजिटल टैक्स नहीं हटाता है, तो वे फ्रांसीसी वाइन और शैंपेन पर 100 फीसद टैरिफ लगा देंगे।

पेरिस अपनी बात पर अड़े रहते हुए कैसे अपनी 'इज्जत बचाएगा', यह अभी साफ नहीं है। यह भी उम्मीद है कि ट्रंप अपने सहयोगियों पर ईरान के साथ भविष्य के समझौते से जुड़े खर्चों को बांटने के लिए दबाव डालेंगे। भारी कर्ज में डूबे देशों से ऐसा करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है, यह भी उतना ही अनिश्चित है। अगस्त, 2025 में अलास्का के एंकरेज में ट्रंप ने रूसी नेता के लिए जो रेड कार्पेट बिछाया था, उसका कोई नतीजा नहीं निकला।

भारतीयता कमजोर होगी सद्भाव पर आंच से

विश्वनाथ सचदेव

युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज समझने वाली बात में अब एक बात और जुड़ गयी है- अब चुनाव में भी सब कुछ सही मान लिया गया है। भले ही हमने अपने संविधान में धर्म-निरपेक्षता के सिद्धांत में विश्वास जताया हो, पर धर्म की दुहाई देकर राजनीतिक स्वार्थ साधने के उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। हाल ही में हुए पांच राज्यों के चुनावों में हमने देखा कि धर्म की राजनीति करने वाले हमारे राजनेताओं को जरा भी संकोच नहीं हुआ। असम और बंगाल में यह प्रकृति खुलकर सामने आयी। खुलेआम धर्म के नाम पर वोट मांगे गये, और धर्म के नाम पर वोट देने वालों की भी कमी नहीं रही। बहुत पुरानी बात नहीं है जब भाजपा के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निस्संकोच यह कहा था कि उन्हें, यानी उनकी पार्टी को मुसलमानों के वोटों की कोई आवश्यकता नहीं है।

उनकी इस बात के पीछे का गणित बहुत स्पष्ट था। देश में मुसलमानों की आबादी लगभग बीस प्रतिशत है। यदि शेष अस्सी प्रतिशत में से पचास-साठ प्रतिशत मतदाता भी धर्म के आधार पर वोट देते हैं तो धर्म की राजनीति करने वालों की विजय सुनिश्चित है। पिछले सात-आठ दशकों में देश के बहुसंख्यक मतदाताओं को धर्म के नाम पर वोट देने के लिए उकसाने की कोशिशों से कौन अपरिचित है? पर यह भी एक वास्तविकता है कि इस देश के बहुसंख्यकों ने सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करने वालों को स्वीकार नहीं किया। इसके बावजूद धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों की कोशिशें लगातार जारी रही हैं। इन कोशिशों को असफल बनाना देश के बेहतर कल की एक प्रमुख शर्त है। हमारे संविधान-निर्माता इन कोशिशों के खतरों को अच्छी तरह समझते थे। इसीलिए हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के आमुख में स्वतंत्रता, समता और न्याय के साथ भाई-चारे को जोड़ना जरूरी समझा था। वे अच्छी तरह जानते थे कि यदि भारत सामाजिक जनतंत्र को स्थापित करने में विफल रहता है तो हमारा राजनीतिक जनतंत्र भी बिखर जायेगा।

संविधान-सभा में 25 नवम्बर, 1949 के अपने भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने यह बात बड़ी स्पष्टता और गंभीरता के साथ समझायी थी। उन्होंने कहा था कि जनतंत्र के चारों आधारों—समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता- का बने रहना जनतांत्रिक भारत के अस्तित्व की शर्त है। वे यह मानते थे कि यदि इन चारों में से किसी एक को भी अपनी जगह से हटाया गया तो जनतंत्र का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा। उन्होंने कहा था, 'स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, न ही समानता को स्वतंत्रता से दूर किया जा सकता है। इसी तरह स्वतंत्रता और समानता को भाई-चारे से पृथक नहीं किया जा सकता। यदि समानता नहीं रही तो 'बहुतों' पर 'कुछ' को वरीयता मिल जायेगी। स्वतंत्रता के बिना समानता का मतलब व्यक्ति की पहल करने की क्षमता को नकारना होगा।' जहां तक भाई-चारे का सवाल है इसका सीधा-सा मतलब है सभी भारतीयों का एक-दूसरे से जुड़ा होना और जुड़ा रहना। उन्होंने इसके साथ ही यह कहना भी जरूरी समझा था कि इसके बिना स्वतंत्रता और समानता का अधिकार भी बहुत ज्यादा माने नहीं रखता। संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर इस विचार को रेखांकित करने वाले अकेले नहीं थे। और भी कइयों ने स्वतंत्र जनतांत्रिक भारत में भाई-चारे की आवश्यकता और महत्ता को रेखांकित किया था।

वे सब इस बात को मानते थे कि भाई-चारा ही वह गोंद है जो भारतीयों को जोड़े रखेगी। बहुधर्मीय, बहुजातीय और बहुभाषी भारत को आपसी भाई-चारे की भावना ही जोड़े रख सकती है। आजादी की अब तक की यात्रा में यदि हम सब एक साथ आगे बढ़ पाये हैं तो उसका श्रेय भी भाई-चारे को समता, स्वतंत्रता और न्याय जितना महत्व देने को जाता है। यह भाई-चारा हमारे संविधान-निर्माताओं के लिए कोई मोहक कल्पना नहीं था, एक ठोस आधार था देश के भविष्य का। सब जानते हैं कि जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो वह समय देश में भारी उथल-पुथल का था। विभाजन की त्रासदी को झेल रहा था देश, सांप्रदायिकता की आंच भी जब-तब सिर उठा रही थी। उस माहौल में भाई-चारे के दार्शनिक विचार को जनता के मन और मस्तिष्क तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था। एक तरफ हमारे संविधान-निर्माता यह काम करने में लगे थे, वहीं दूसरी ओर बंगाल में महात्मा गांधी अपनी 'एक व्यक्ति की सेना' के सहारे सांप्रदायिकता की आग बुझाने का काम कर रहे थे।

यह तथ्य कम महत्वपूर्ण नहीं है कि जिस दिन राजधानी दिल्ली में यूनियन जैक को उतार कर तिरंगा फहराया जा रहा था, महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों मील दूर बंगाल में थे। गांधी अच्छी तरह समझते थे कि बंधुता को जिये बिना देश में सही अर्थों में जनतंत्र नहीं आ सकता। आज इस बात को फिर से समझने की आवश्यकता है कि गांधी ने 15 अगस्त, 1947 को दिल्ली के बजाय कोलकाता में रहना जरूरी क्यों समझा था। आज फिर उस भाई-चारे को समझने-जीने की आवश्यकता है। असम, बंगाल जैसे राज्यों में हाल के चुनावों में हमने देखा है कि किस तरह सांप्रदायिकता की आंच को हवा देने का काम हुआ है। धर्म के नाम पर वोट मांगना, और वोट दिया जाना, देश के संविधान को नकारना, उसका अपमान करना है। पर यह काम हुआ। हमारे संविधान-निर्माताओं ने धर्म के आधार पर वोटों के बंटवारे को नकार कर स्पष्ट कर दिया था कि धर्म-निरपेक्ष, जनतांत्रिक भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

योग

शरीर और मन को करता है संतुलित

हर साल की तरह इस बार भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारतीय संस्कृति से उपजी योग की एक प्राचीन प्रथा है, जो किसी भी व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक अस्तित्व को बढ़ावा देने के साथ-साथ तन और मन को संतुलित करने के लिए जानी जाती है। भारतीय संस्कृति से उपजी योग की प्राचीन प्रथा व्यापक रूप से किसी व्यक्ति के शरीर और मन को संतुलित करने के लिए जानी जाती है। योग शक्ति और लचीलापन बनाने में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और तनाव प्रबंधन निमित एक शानदार उपकरण है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 'योग का सार संतुलन है' यह न केवल शरीर को स्वस्थ एवं फुर्तीला बनाता है, दुनिया के साथ मानवीय संबंधों में भी संतुलन का प्रतीक है। योग ध्यान, संयम, अनुशासन और दृढ़ता के मूल्यों पर जोर देता है।

योग दिवस का महत्व

इस वर्ष दुनिया भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस दिन लोग पार्क अथवा किसी खुले स्थान पर एकत्र होकर सामूहिक रूप से योग के विभिन्न आसन करते हैं। योग के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। मान्यता है कि योग की उत्पत्ति हजारों साल पहले भारत में हुई थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद जैसी प्राचीन पौराणिक पुस्तकों में भी मिलता है। प्रतिदिन योग का अभ्यास करने से मनुष्य के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे शरीर में लचीलापन, मांसपेशियों की ताकत और बॉडी टोन बढ़ाने में भी मदद करता है। योग के विभिन्न आसनों से श्वसन, ऊर्जा और जीवन शैली में सुधार आता है। यह तनाव और चिंता को आपके अनुरूप मैनेज करने में मदद करता है और तनाव मुक्त रखता है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इतिहास

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 सितंबर, 2014 को आया, जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान प्रस्तावित किया था। इसके बाद, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक मसौदा संकल्प संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत अशोक कुमार मुखर्जी द्वारा पेश किया गया था। इस मसौदे को 177 देशों से समर्थन प्राप्त हुआ। यह भारत के लिए गौरव की बात थी, जो किसी भी यूएनजीए प्रस्ताव के लिए सह-प्रायोजकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करते हुए पहली बार आयोजन किया गया। जो आज भी विश्वव्यापी समर्थन के साथ जारी है।

क्या है योग

योग शारीरिक व्यायाम, शारीरिक मुद्रा (आसन), ध्यान, सांस लेने की तकनीकों और व्यायाम को जोड़ता है। इस शब्द का अर्थ ही योग या भौतिक का स्वयं के भीतर आध्यात्मिक के साथ मिलन है। यह सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना के मिलन का भी प्रतीक है, जो मन और शरीर, मानव और प्रकृति के बीच एक पूर्ण सामंजस्य का संकेत देता है।

योग दिवस 2026 की थीम

प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक खास विषय पर आधारित होता है। वर्ष 2026 में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आधिकारिक थीम स्वास्थ्य, ज्ञान और विश्व शांति के लिए योग है। आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित यह विषय वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, शारीरिक कल्याण और आंतरिक संतुलन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। स्वास्थ्य योग शरीर को मजबूत बनाने के साथ-साथ जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से बचाव करने में मदद करता है। ज्ञान अभ्यास मन की एकाग्रता, आत्म-जागरूकता और विचारों की स्पष्टता को बढ़ाता है। विश्व शांति आंतरिक शांति के माध्यम से एक सामंजस्यपूर्ण और शांत समाज के निर्माण को बढ़ावा मिलता है।

योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है

21 जून की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह ग्रीष्म संक्रांति है, जिस दिन साल के हर दूसरे दिन में सबसे ज्यादा सूरज निकलता है। 21 जून, 2015 को, प्रधानमंत्री मोदी सहित लगभग 36,000 लोगों और दुनिया भर के कई अन्य हाई-प्रोफाइल राजनीतिक हस्तियों ने नई दिल्ली में 35 मिनट के लिए 21 आसन (योग आसन) किए, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था।

हंसना मना है

12 साल बाद एक व्यक्ति जेल से छूटा था तो वह मैले कुचैले कपड़ों में बहुत थका हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचते ही बीबी चिल्लाई- कहां घूम रहे थे इतनी देर? आपकी रिहाई तो 2 घंटे पहले ही हो गई थी ना? वो आदमी वापस जेल चला गया।

रमेश (नौकर से)- जरा देख तो बाहर सूरज निकला या नहीं? नौकर - बाहर तो अंधेरा है। संता - अरे! टॉर्च जलाकर देख ले कामचोर।

पत्नी- सुनो, आजकल चोरियां बहुत होने लगी हैं। धोबी ने हमारे दो तौलिया चुरा लिए हैं। पति- कौन से तौलिये? पत्नी - अरे! वही जो हम मनाली के होटल से उठाकर लाए थे।

सास- जमाई राजा अगले जन्म में आप क्या बनोगे? जमाई- सासू मां मैं अगले जन्म में छिपकली बनूंगा। सास- छिपकली क्यूं? जमाई- क्योंकि मेरी बीवी छिपकली से बहुत डरती है।

मरीज-डॉक्टर साहब, मेरी दाई टांग में बहुत दर्द रहेता है? डॉक्टर-ये उम्र का तकाजा है? मरीज-लेकिन मेरी बाई टांग की भी तो उम्र उतनी ही है? फिर दाई टांग में ही तकलिफ क्यों? डाक्टर बेहोश!!

कहानी — नकली तोता

एक घने जंगल में विशाल बरगद के पेड़ पर बहुत सारे तोते रहा करते थे। उन्हीं में एक मिट्टू नाम का तोता भी था। वह बहुत कम बोलता था। इससे सब उसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन वह कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। एक दिन दो तोते आपस में बात कर रहे थे। पहला बोला-मुझे एक बार बहुत अच्छा आम मिला था। दूसरे ने जवाब दिया- मुझे भी एक दिन आम का फल मिला था, मैंने भी बड़े चाव से उसे खाया था। वहीं, मिट्टू तोता चुपचाप बैठा था। तब मुखिया ने कहा- अरे हम तोतों का तो काम ही होता है बात करना, तुम क्यों चुप रहते हो? तुम तो मुझे असली तोते लगते ही नहीं। तुम नकली तोते हो। इस पर सभी उसे नकली तोता कहकर बुलाने लगे। फिर एक दिन रात में मुखिया की बीवी का हार चोरी हो गया। मुखिया की बीवी ने कहा- वो हमारी ही झुंड में से एक है। मुखिया ने तुरंत सभा बुलाई। मुखिया ने कहा- मेरी बीवी ने उस चोर को भागते हुए भी देखा है। वह चोर आप लोगों में से ही कोई एक है। उसने मुंह को कपड़े से ढककर रखा हुआ था, लेकिन उसकी चोंच बाहर दिख रही थी। उसकी चोंच लाल रंग की थी। अब सभी की निगाह मिट्ठू तोते और हीरू नाम के एक दूसरे तोते पर थी, क्योंकि इन्हीं दोनों की चोंच लाल रंग की थी। मुखिया ने सोचा कि ये दोनों मेरे अपने हैं। इसलिए, मुखिया ने एक कौवे से इसका पता लगाने के लिए मदद ली। कौवे ने लाल चोंच वाले हीरू और मिट्टू तोते को बुलाया। कौवे के पूछने पर हीरू तोता बोला मैं उस दिन बहुत थक गया था। इसलिए, खाना खाकर सोने के लिए चला गया था। वहीं मिट्ठू तोते ने कहा-मैं उस रात सो रहा था। कौवे ने फिर पूछा- तुम दोनों अपनी बात साबित करो। हीरू बोला-मैं रात सो रहा था। सब जानते हैं। ये चोरी मिट्टू ने ही की होगी। मिट्ठू बोला- मैंने यह चोरी नहीं की है। कौवा बोला कि चोर का पता लग गया है। कौवे ने बताया कि चोरी हीरू तोते ने की है। मुखिया ने पूछा- आप यह कैसे कह सकते हैं? कौवे ने कहा- हीरू जोर-जोर से बोलकर झूठ को सच साबित करने में लगा था, जबकि मिट्टू सच बोल रहा है। इसलिए आराम से कह रहा था। इसके बाद हीरू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी से माफी मांगी। यह सुनकर सभी तोते हीरू तोते को कड़ी सजा देने की बात कहने लगे, लेकिन मिट्टू तोते ने कहा- मुखिया जी, हीरू तोते ने अपनी गलती मान ली है। उसने सबके सामने माफी भी मांग ली है। उससे पहली बार यह गलती हुई है, इसलिए उसे माफ किया जा सकता है। यह बात सुनने के बाद मुखिया ने हीरू तोते को माफ कर दिया।

7 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद् हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष — नौकरी में प्रभाव वृद्धि होगी। बिगड़े काम बनेंगे। निवेश मनोनुकूल लाभ देगा। सामाजिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। घर-बाहर पूछ-परख रहेगी।

वृषभ — राजकीय सहयोग प्राप्त होगा। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। नौकरी में सहकर्मी साथ देंगे। कारोबार में वृद्धि होगी। निवेश लाभ देगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मिथुन — किसी व्यक्ति की बातों में न आएं। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। चिंता तथा तनाव बने रहेंगे। वाहन, मशीनरी व अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें।

कर्क — राजकीय सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है। व्यापार में वृद्धि होगी। स्त्री वर्ग से समयानुकूल सहायता प्राप्त होगी। नौकरी में उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे।

सिंह — आर्थिक उन्नति के प्रयास सफल रहेंगे। कर्ज समय पर चुका पाएंगे। बैंक-बैलेंस बढ़ेगा। स्थायी संपत्ति के बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं। मनपसंद रोजगार मिलेगा।

कन्या — यात्रा लाभदायक रहेगी। बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है।

तुला — व्यापार-व्यवसाय से लाभ होगा। आय में निश्चितता रहेगी। शत्रु शांत रहेंगे। बुरी खबर मिल सकती है, धैर्य रखें। दौड़धूप की अधिकता का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा।

वृश्चिक — थोड़े प्रयास से ही कार्यसिद्धि होने से प्रसन्नता रहेगी। निवेश से लाभ होगा। व्यापार-व्यवसाय ठीक चलेंगे। आवश्यक वस्तु समय पर नहीं मिलने से खिन्नता रहेगी।

धनु — शुभ समाचार प्राप्त होंगे। प्रसन्नता रहेगी। बिछड़े मित्र व संबंधी मिलेंगे। विरोधी सक्रिय रहेंगे। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। व्यापार मनोनुकूल चलेगा।

मकर — व्यावसायिक यात्रा लाभदायक रहेगी। रोजगार मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। कारोबार में वृद्धि होगी। शेयर मार्केट मनोनुकूल लाभ देगा। बुद्धि का प्रयोग करें।

कुम्भ — नौकरी में कार्यभार रहेगा। थकान महसूस होगी। आंखों का विशेष ध्यान रखें। चोट व रोग से बचाएं। पुराना रोग उभर सकता है। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें।

मीन — रुका हुआ धन प्राप्त होगा। प्रयास सफल रहेंगे। बुद्धि का प्रयोग करें। प्रमाद न करें। निवेश से लाभ होगा। यात्रा मनोनुकूल रहेगी। कारोबार से संतुष्टि रहेगी।

बॉलीवुड | मन की बात

मैं वही करना चाहती हूं जो पहले कभी न किया हो : माधुरी दीक्षित

माधुरी दीक्षित इन दिनों हालिया रिलीज फिल्म मां बहन को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने उस दौर को भी याद किया जब इंडस्ट्री में उन्हें सुनना पड़ता था कि ये लड़की नहीं चलेगी। करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए माधुरी ने बताया, जब मैंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, तब मैं उस दौर की बनी-बनाई हीरोइनों जैसी नहीं दिखती थी। इस वजह से कई बातें होती थीं। लोग कहते थे ये बहुत पतली है, ये कैसे चलेगी? नहीं हो पाएगा। लेकिन उस वक्त मेरी मां मेरे साथ खड़ी रही। वो हमेशा एक बात कहती थीं कि लोग आज जिस चीज के लिए तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जब माधुरी से पूछा गया कि क्या कभी उन्होंने खुद असुरक्षा महसूस की? तो अभिनेत्री ने कहा, 'आज मैं खुद के साथ पूरी तरह सहज हूं। लेकिन असुरक्षाएं तब थीं जब मैंने नया-नया काम शुरू किया था। उस समय कुछ लोगों ने मेरे मन में असुरक्षाएं डालने की कोशिश की थी। लेकिन मेरी मां चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ी थीं। वो हर बार मेरी हर असुरक्षा को वहीं खत्म कर देती थीं। फिल्म 'मां बहन' के बाद कहा जा रहा है कि क्या माधुरी अपनी एक नई पहचान गढ़ रही हैं? इसके जवाब में एक्ट्रेस ने कहा, 'ऐसा कुछ नहीं है। जब लोग मुझे धक धक गर्ल कहते थे, तब भी मैंने मृत्युदंड', 'पुकार' और 'लज्जा' जैसी फिल्में की थीं। मैं हमेशा वही करना चाहती हूं जो मैंने पहले कभी न किया हो। यही चीज मुझे आगे बढ़ाती है। मैं हमेशा खुद को बदलते रहना चाहती हूं। अगर लोगों को अब ऐसा लग रहा है तो मुझे खुशी है।' बदलते सिनेमा पर माधुरी ने कहा, 'मुझे लगता है दोनों दौर आसान नहीं हैं। बड़े पर्दे की फिल्म बनाते वक्त सबसे बड़ा दबाव यही होता है कि वह हर तरह के दर्शकों को पसंद आए। अलग-अलग सोच, अलग-अलग तबके, अलग-अलग माहौल..., सबको जोड़ना पड़ता है, तभी लोग थिएटर तक आते हैं।

प्रेग्नेंट महिला के किरदार में दिखीं श्रद्धा कपूर, 'ईथा' के टीजर ने मचाई सनसनी

श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। फैंस लंबे वक्त से हसीना को पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं। अब श्रद्धा कपूर एक बार फिर सिनेमाघरों में धमाका करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। श्रद्धा की मच अवेटेड फिल्म ईथा को लेकर काफी वक्त से चर्चा चल रही थी। अब इसी बीच फिल्म का फर्स्ट लुक आउट हो चुका है। श्रद्धा कपूर की ईथा का टीजर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनका बेहद दमदार लुक देखने को मिल रहा है। ईथा का टीजर कॉकटेल 2 के साथ रिलीज किया गया, जिसके बाद लोगों ने इसे इंटरनेट पर वायरल कर दिया।

श्रद्धा कपूर की फिल्म ईथा का पहला टीजर कॉकटेल 2 के साथ सिनेमाघरों में दिखाए जाने के कुछ ही समय बाद ऑनलाइन लीक हो गया, जिसे देखकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है। यह टीजर शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर कॉकटेल 2 के साथ दिखाया गया था, जो आज 19 जून को देशभर के थिएटरों में

रिलीज हुई है। ईथा के इस टीजर में श्रद्धा कपूर का वह अंदाज देखने को मिला है, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया।

वायरल हो रहे इस टीजर में ईथा में श्रद्धा कपूर ट्रेडिशनल साड़ी लुक में नजर आ रही हैं। क्लिप की शुरुआत श्रद्धा के प्रेग्नेंट महिला के किरदार से होती है। इस टीजर में श्रद्धा को लेबर पेन से गुजरते हुए दिखाया गया है और फिर बाद के सीन्स में श्रद्धा एक डांसर के तौर पर नजर आती हैं। इस क्लिप को देखने के बाद फैंस उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं और फिल्म देखने के लिए बेताब हैं।

बता दें कि श्रद्धा कपूर की फिल्म ईथा विठाबाई नारायणगांवकर की बायोपिक है, जिन्हें तमाशा क्वीन के नाम से भी जाना जाता है और जो महाराष्ट्र की लोक-नाट्य परंपरा में एक मशहूर हस्ती रही हैं। इस फिल्म में श्रद्धा लीड रोल में नजर आएंगी और उनके साथ रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब भी अहम रोल में नजर आएंगे। म्यूजिक कंपोजर अतुल-अजय ने इस म्यूजिकल पीरियड ड्रामा के लिए संगीत तैयार किया है, जिसकी कहानी 1950 और 1980 के दशक के बीच की है। इस बायोपिक का डायरेक्शन लक्ष्मण उतेकर कर रहे हैं और इसे दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है। सिनेमाघरों में यह फिल्म 28 अगस्त को रिलीज होगी।

एडवांस बुकिंग में ही कॉकटेल 2 ने कर डाली तगड़ी कमाई

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर कॉकटेल 2 फाइनली शुक्रवार, 19 जून यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस रोमांटिड ड्रामा का रिलीज से पहले ही काफी बज बना हुआ है जिसके चलते इसकी धुआंधार एडवांस बुकिंग हुई है। चलिए यहां जान लेते हैं कि कॉकटेल 2 ने अपनी प्री टिकट सेल से कितने करोड़ कमा लिए हैं?

2012 की हिट फ़िल्म कॉकटेल का स्पिरिचुअल सीक्वल बॉलीवुड फ़ैन्स के लिए वाकई एक बड़ा जश्न है। मैडॉक फिल्म्स के इस प्रोडक्शन से काफ़ी उम्मीदें हैं, इसे एडवांस बुकिंग में अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इसने है जवानी तो इश्क़ होना है को पीछे छोड़ते हुए 2026

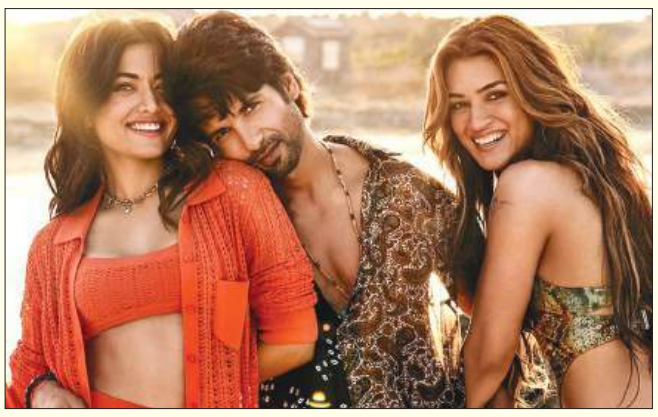

की टॉप 5 बॉलीवुड प्री-सेल्स फ़िल्मों में जगह बना ली है। फिल्म के एडवांस बुकिंग की बात करें तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक<फिल्म के हिंदी 2ष वर्जन ने देश भर में 11,868 शो में 1 लाख 61 हजार 547 टिकटों की सेल की है जिससे इसने 5.56 करोड़ रुपये का एडवांस ग्रॉस कलेक्शन किया है। वहीं ब्लॉक की गई सीटों को मिलाकर, फिल्म का कुल एडवांस ग्रॉस कलेक्शन अनुमानित 8.83 करोड़ रुपये है।

महाराष्ट्र अब तक फिल्म का सबसे मज़बूत बाज़ार बनकर उभरा है, जिसने एडवांस बिक्री में 1.46 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रिब्यूशन दिया है। ब्लॉक की गई सीटों को शामिल करने पर यह कलेक्शन बढ़कर अनुमानित 1.98 करोड़ रुपये हो जाता है वहीं दिल्ली 1.09 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग के साथ ठीक पीछे है, जो ब्लॉक की गई सीटों के साथ बढ़कर 1.71 करोड़ रुपये हो जाती है। कर्नाटक टॉप 3 में शामिल है, जिसने एडवांस बिक्री में 65.47 लाख रुपये कमाए, वहीं ब्लॉक की गई सीटों को मिलाकर यह आंकड़ा अनुमानित 95.32 लाख रुपये तक पहुंच जाता है।

अजब-गजब | इसे देवभूमि के साथ-साथ कहा जाता है पर्वतों की धरती

भारत के इस राज्य में हैं सबसे ज्यादा पहाड़

जब भी भारत के सबसे ज्यादा पर्वतीय राज्य की बात होती है, तो ज्यादातर लोग उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर या सिक्किम का नाम लेते हैं। ऊंची-ऊंची बर्फीली चोटियों और प्रसिद्ध हिमालयी स्थलों के कारण ये राज्य लोगों के मन में सबसे पहले आते हैं। हालांकि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा पर्वतीय क्षेत्र वाला राज्य हिमाचल प्रदेश माना जाता है। यही वजह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान से जुड़े सवालों में यह प्रश्न अक्सर लोगों को भ्रमित कर देता है।

हिमाचल प्रदेश का ज्यादातर भूभाग पहाड़ों से घिरा हुआ है। राज्य का करीब 90 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र में आता है। यही कारण है कि इसे देवभूमि के साथ-साथ पर्वतों की धरती भी कहा जाता है। यहां की भौगोलिक संरचना बेहद विविध और आकर्षक है। हिमाचल का क्षेत्र बाहरी हिमालय, मध्य हिमालय और महान हिमालय जैसी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में फैला हुआ है, जो इसे प्राकृतिक रूप से बेहद समृद्ध बनाती हैं।

राज्य की ऊंचाई कुछ स्थानों पर समुद्र तल से लगभग 350 मीटर से शुरू होकर 7,000 मीटर के आसपास तक पहुंच जाती है। यहां बर्फ से ढकी चोटियां, गहरी घाटियां, विशाल ग्लेशियर और तेज बहती नदियां प्राकृतिक सौंदर्य को और खास बनाती हैं। सतलुज, रावी और चेनाब जैसी महत्वपूर्ण नदियां भी इसी क्षेत्र से होकर गुजरती हैं और प्रदेश की पहचान का हिस्सा हैं।

कई लोग यह मानते हैं कि उत्तराखंड या लद्दाख में मौजूद ऊंची चोटियां ही किसी राज्य को सबसे पर्वतीय बनाती हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार केवल ऊंचाई नहीं बल्कि पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार और घनत्व भी महत्वपूर्ण होता है। उत्तराखंड में नंदा देवी जैसी प्रसिद्ध चोटियां हैं, जबकि लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में दुनिया की कुछ सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं। इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश का बड़ा हिस्सा लगातार पर्वतीय भूभाग से ढका हुआ है, जो इसे अलग पहचान देता है।

पर्यटन के लिहाज से भी हिमाचल प्रदेश देश के सबसे लोकप्रिय राज्यों में गिना जाता है। शिमला, मनाली, डलहौजी, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे स्थान हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ी संस्कृति, पारंपरिक त्योहार और स्थानीय भाषाएं इस राज्य को और खास बनाती हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन का असर यहां भी दिखाई देने लगा है। ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, भूस्खलन की बढ़ती घटनाएं और मौसम में बदलाव भविष्य के लिए चिंता का विषय हैं। इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश आज भी भारत की प्राकृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां पर्वत सिर्फ भौगोलिक पहचान नहीं बल्कि लोगों की जीवनशैली और संस्कृति का अभिन्न अंग हैं।

दुनिया का वो देश, जहां गली-गली बिकता है गांजा, इंसानों से अधिक है गाय की संख्या!

अगर कोई देश हो जहां गांजा खरीदना-बेचना पूरी तरह कानूनी हो, पुलिस आपको नहीं पकड़े बल्कि सरकार खुद दुकानें चलाए, समलिंगी शादी हो, एबॉर्शन हो और भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज ना हो तो आप किस देश की कल्पना करेंगे? यह कोई काल्पनिक जगह नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका का छोटा सा देश ruguay है, जिसे दुनिया का सबसे शांत और प्रगतिशील देश कहा जाता है। वर्ष 2013 में उरुग्वे दुनिया का पहला देश बना जिसने पूरे देश में गांजा पूरी तरह कानूनी बना दिया। यहां गांजा ना सिर्फ लीगल है बल्कि फार्मेसी और लाइसेंस्ड दुकानों पर खुलेआम बिकता है। सरकार खुद इसकी खेती, उत्पादन और बिक्री नियंत्रित करती है। इसका मकसद था- अवैध माफिया और ड्रग कार्टल को खत्म करना और टैक्स के रूप में सरकार को राजस्व देना। आज Uruguay में 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से गांजा खरीद, रख और इस्तेमाल कर सकता है। पर्यटक भी सीमित मात्रा में ले सकते हैं। पुलिस नशे की जांच नहीं करती बल्कि ट्रैफिक नियमों पर ध्यान देती है। उरुग्वे में लगभग 34 लाख इंसान रहते हैं जबकि गायों की संख्या 1.2 करोड़ से ज्यादा है। यानी हर इंसान पर औसतन 3-4 गायें हैं। यहां मांस निर्यात बहुत बड़ा उद्योग है। बीफ की गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि दुनिया भर में मशहूर है। उरुग्वे कई सामाजिक मुद्दों पर बहुत आगे है। यहां सेम सेक्स मैरिज 2013 में ही लीगल कर दिया गया था। इसके अलावा 2012 से महिलाओं को पहली 12 हफ्तों तक एबॉर्शन का अधिकार है। इस देश में भ्रष्टाचार ना के बराबर है। Transparency International के अनुसार उरुग्वे लैटिन अमेरिका का सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है। यहां राजनेता और अधिकारी काफी ईमानदार माने जाते हैं। वहीं संसद में महिलाओं की अच्छी भागीदारी है शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरह मुफ्त है। 90% से ज्यादा आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। देश में बहुत कम अपराध दर है। लोग बेहद शांत और खुशहाल जीवन जीते हैं। इसी वजह से इसे WorldÓs Most Chill Country भी कहा जाता है। उरुग्वे की सफलता का राज उसकी छोटी आबादी और मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा है। 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति Jose Mujica (जिन्हें दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रपति कहा जाता था) ने गांजा लीगलाइजेशन का ऐतिहासिक फैसला लिया। उनका मानना था कि नशे से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका उसे नियंत्रित करना है, ना कि प्रतिबंध लगाना। आज कई देश उरुग्वे के इस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। कनाडा, थाईलैंड, जर्मनी और कई अमेरिकी राज्य अब इसी रास्ते पर चल रहे हैं।

पेंशन को लेकर ओडिशा में सियासी टेंशन

बीजेपी सरकार ने सबसे कमजोर नागरिकों को मुश्किल में डाला : नवीन

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा मैं पूरे ओडिशा में लगभग 18 लाख लाभार्थियों को पिछले तीन महीनों से पेंशन न मिलने पर गहरी चिंता और दुख के साथ यह पत्र लिख रहा हूँ। इन पेंशनभोगियों में हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्ग शामिल हैं - जैसे बुजुर्ग नागरिक, विधवाएँ और दिव्यांग लोग - जिनमें से ज़्यादातर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए पूरी तरह से इसी पेंशन पर निर्भर हैं। लगातार तीन महीनों तक इस ज़रूरी मदद के न मिलने से हमारे सबसे कमज़ोर नागरिक भारी परेशानी, अभाव और यहाँ तक कि भुखमरी के जोखिम का सामना कर रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि गंजाम के बेगुनियापाडा की श्रीमती सबित्री डोरा की पेंशन लाभ न मिलने के कारण मौत हो गई। अपने सबसे कमज़ोर नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध राज्य में ऐसी स्थिति स्वीकार्य नहीं है।

» राज्य भर के 18 लाख लाभार्थियों को पिछले तीन महीनों से पेंशन न मिलने पर भड़के पूर्व सीएम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

भुवनेश्वर। ओडिशा में विपक्ष के नेता और बीजू जनता दल (बीजद) के प्रमुख नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को पत्र लिखकर राज्य भर के 18 लाख लाभार्थियों को पिछले तीन महीनों से पेंशन न मिलने का मुद्दा उठाया। अपने पत्र में पटनायक ने कहा कि इस समस्या ने ओडिशा के सबसे कमज़ोर नागरिकों को मुश्किल में डाल दिया है, जो अब भारी परेशानी, अभाव और भुखमरी के जोखिम का सामना कर रहे हैं। उन्होंने गंजाम की एक महिला पेंशनभोगी की मौत की ओर भी ध्यान दिलाया, जिसकी कथित तौर पर पेंशन लाभ न मिलने के कारण मौत हो गई।

अपने कार्यकाल के दौरान हर महीने की 15 तारीख को सभी लाभार्थियों को पेंशन ट्रांसफर करने की पारदर्शी प्रक्रिया का जिक्र करते हुए, बीजद प्रमुख ने कहा कि मौजूदा समस्या एक सॉफ्टवेयर से जुड़ी दिक्कत के कारण हुई है। हैरानी की बात यह है कि खबरों के मुताबिक, इतनी लंबी देरी सॉफ्टवेयर से जुड़ी समस्या की वजह से हुई है। यह घोर लापरवाही और सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने जैसा है। लोगों के अधिकारों को तकनीकी खराबी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। यह याद रखना ज़रूरी है कि पिछले 24 सालों से मेरी सरकार ने यह पक्का किया कि हर महीने की 15 तारीख को पेंशन नियमित रूप से बांटी जाए, जिसे जन सेवा दिवस के तौर पर मनाया जाता था। लाभार्थियों को ग्राम पंचायत स्तर पर पारदर्शी और मानवीय तरीके से पेंशन मिलती थी। जिन मामलों में पेंशनभोगी खुद नहीं आ पाते थे, वहां अधिकारी यह पक्का करते थे कि पेंशन की रकम सीधे उनके घर पहुंचाई जाए।

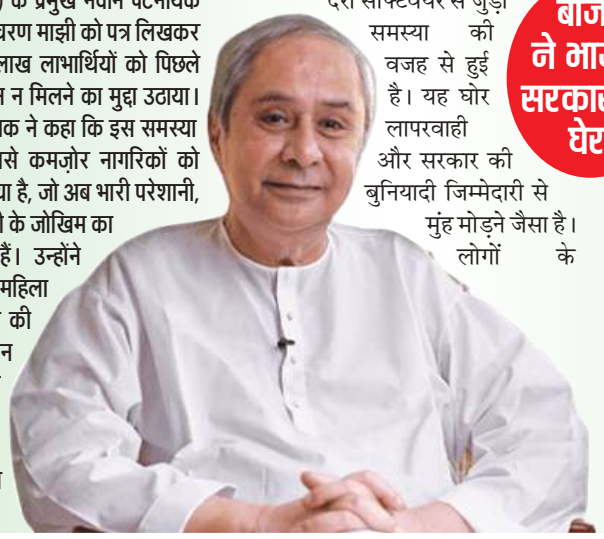

बीजद ने भाजपा सरकार को घेरा

टीएमसी के बागी सांसदों ने बेची ईमानदारी : अभिषेक बनर्जी

» टीएमसी सांसद लोस स्पीकर से मिले

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस ने बागी सांसदों के खिलाफ अपनी लड़ाई को राष्ट्रीय राजधानी तक पहुँचा दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और 20 टीएमसी सांसदों के नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया में विलय के मुद्दे पर चर्चा की। कोलकाता में पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी से बातचीत के बाद, बनर्जी वरिष्ठ नेताओं डेरेक ओ-ब्रायन और सौगत रॉय के साथ दिल्ली पहुंचे। इस घटनाक्रम से टीएमसी के सामने चल रहे राजनीतिक संकट में और तेज़ी आ गई है।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने के बाद, टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि टीएमसी के 20 सांसदों ने 3-4 दिन पहले स्पीकर से मुलाकात की और अपना अलग गुट बनाने का दावा किया। मीडिया के अनुसार, उन्होंने एक अलग गुट के तौर पर माने जाने का दावा किया है। फिर कुछ घंटों बाद उनमें से 2-4 लोगों ने एनसीपीआई में विलय का दावा किया, जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना था। टीएमसी के लोकसभा नेता के तौर पर, मैंने अयोग्यता की 20 अलग-अलग याचिकाएं

सौंपी हैं... 10 वीं अनुसूची उनके खिलाफ है, उन लोगों के खिलाफ जो अलग गुट बनाने का दावा करते हैं। अगर उनमें थोड़ी भी ईमानदारी है, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इन 20 (बागी सांसदों) ने लोगों को धोखा दिया और संविधान का अनादर व अपमान किया। उन्होंने अपनी अंतरात्मा, सम्मान और ईमानदारी बेच दी है। बंगाल की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इनमें से कई (बागी सांसदों) को केंद्रीय सुरक्षा दी गई है। उनके निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति उनके साथ खड़ा नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हमें बिल्कुल भी बराबरी का मौका नहीं मिल रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पार्टियां तोड़ी जा रही हैं सिर्फ़ बंगाल में ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में भी। शिवसेना के दो टुकड़े कर दिए गए और अब दूसरे हिस्से को भी अपने फ़ायदे के लिए और तोड़ा जा रहा है।

दो हार के बाद न्यूजीलैंड ने खोला जीत का खाता

» महिला टी20 विश्व कप: आयरलैंड को रोमांचक मुकाबले में 4 रन से हराया

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

साउथैम्पटन। महिला टी20 विश्व कप 2026 में न्यूजीलैंड ने रोमांचक मुकाबले में आयरलैंड को चार रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। साउथैम्पटन में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 140 रन बनाए, जिसके जवाब में आयरलैंड की टीम 136/4 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने टूर्नामेंट में अपना जीत का खाता खोला। वहीं, आयरलैंड को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा। ग्रुप-दो में आयरलैंड सबसे निचले स्थान पर बनी हुई है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम चौथे स्थान पर पहुंच गया है।

टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम ने न्यूजीलैंड को शुरुआती झटके दिए। टीम का स्कोर महज 10 रन पर तीन विकेट हो गया था। इसके बाद कप्तान अमेलिया केर ने 24 गेंदों में 30 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की। ब्रूक हॉलिडे ने 37 गेंदों पर 34 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। इसके बाद इजी शार्प के साथ पांचवें विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। 141 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की शुरुआत खराब रही और एमी हंटर जल्दी आउट हो गईं। इसके बाद कप्तान गैबी लुईस और ऑर्ला प्रेंडरगास्ट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरे विकेट के लिए 110 रन की साझेदारी की। प्रेंडरगास्ट ने 53 गेंदों में 59 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि गैबी लुईस ने भी अर्धशतक जड़ा। दोनों बल्लेबाजों ने आयरलैंड को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया था। जब आयरलैंड जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही थी, तब न्यूजीलैंड की कप्तान अमेलिया केर ने 18वें ओवर में दो महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया। प्रेंडरगास्ट बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हुईं, जबकि दो गेंद बाद रेबेका स्टोकल भी पवेलियन लौट गईं। इसके बाद रोजमेरी मेयर ने गैबी लुईस का विकेट लेकर आयरलैंड की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया।

ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी तय!

नई दिल्ली। आईपीएल 2027 से पहले एक बड़ी ट्रेड डील सामने आ सकती है। ऋषभ पंत की अपने पुराने फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स में वापसी होने की संभावना है। इसके बदले में स्पिनर कुलदीप यादव को लखनऊ सुपर जाएंट्स भेजा जा सकता है। दोनों फ्रेंचाइजियों के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत जारी है और अंतिम मंजूरी बीसीसीआई और आईपीएल प्रशासन की ओर से मिलनी बाकी है। हालांकि, खिलाड़ियों के ट्रांसफर से जुड़ी वित्तीय शर्तों और अन्य औपचारिकताओं पर अभी चर्चा जारी है। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में लखनऊ सुपर जाएंट्स ने ऋषभ पंत को रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपये में खरीदा था। इसके साथ ही वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। दिल्ली कैपिटल्स ने नेतृत्व संबंधी मतभेदों के बाद पंत को रिलीज कर दिया था, जिसके बाद लखनऊ ने उन पर बड़ा दांव लगाया था।

कुछ लोग कुत्ते होते हैं, लेकिन वफादार नहीं

» उद्धव ठाकरे पर शिंदे के तंज के बाद शिवसेना यूबीटी नेता राउत का पलटवार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी संदेश ऐसे समय में आया है जब अटकलें लगाई जा रही हैं कि पार्टी के छह लोकसभा सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। राउत ने हिंदी वाक्यांश कुछ लोग कुत्ते तो होते हैं, लेकिन वफ़ादार नहीं होते वाली एक छवि साझा की, साथ ही कैप्शन दिया, जय महाराष्ट्र! यह पोस्ट ऐसे समय में आई है जब उद्धव बालासाहेब ठाकरे के गुट को एक और बड़े बंटवारे का सामना करना पड़ सकता है।

इससे पहले 2022 में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई में हुई बगावत ने पार्टी का स्वरूप बदल दिया था।

गुरुवार को राजनीतिक संकट तब और गहरा गया जब शिवसेना (यूबीटी) के नौ लोकसभा सांसदों में से छह सांसद नई दिल्ली में संसद परिसर में बुलाई गई संसदीय दल की बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक में शामिल न होने वाले सांसदों में नागेश आष्टिकर, संजय देशमुख, संजय जाधव, संजय दीना पाटिल, ओमप्रकाश राजेनिंबालकर और भाऊसाहेब वाकचौरे शामिल थे। उनके न आने पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने सांसदों पर पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा की। राउत ने कहा जो लोग कभी खुद को शिवसैनिक कहते थे, वे कायर हैं। सच्चे शिवसैनिक कायर नहीं होते। अगर उन्हें अपने रुख पर भरोसा है, तो वे जयपुर में क्यों छिपे हुए हैं?

उद्धव गुट ने बागी सांसदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस, 24 घंटे का दिया समय

पार्टी से बागी सांसदों को चीफ सेक्रेटरी अनिल देसाई ने व्हिप जारी होने के बाद भी बैठक में शामिल न होने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके लिए सभी सांसदों को 24 घंटे का समय दिया गया है आदेश में कहा गया है कि पार्टी व्हिप मिलने के बावजूद मंगलवार को हुई लोकसभा सांसदों की बैठक में मौजूद न रहने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया जा रहा है। नोटिस में लिखा गया कि जरूरी मीटिंग का बताने के बावजूद आप इस बैठक से गायब थे।

हरियाणा में कानून व्यवस्था ताक पर, बदमाश बेखौफ

» पुलिस स्टेशन के सामने कांग्रेस एमएल के ऑफिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

रोहतक। हरियाणा के रोहतक जिले में शनिवार सुबह महम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमलावरों द्वारा चलाई गई गोलियां दफ्तर के शीशों को चीरती हुई पार निकल गईं, जिससे मौके पर कांच के टुकड़े बिखर गए।

विधायक का यह कार्यालय महम पुलिस स्टेशन के ठीक सामने स्थित है। पुलिस की नाक के नीचे एक जनप्रतिनिधि के दफ्तर पर दिनदहाड़े हुई इस दुस्साहसिक वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

क्रॉस-वोटिंग से भाजपा परेशान

» बीजेपी अध्यक्ष ने विजयेंद्र को किया तलब

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

बेंगलुरु। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में भाजपा और जद(एस) विधायकों की व्यापक क्रॉस-वोटिंग ने दोनों दलों में संगठनात्मक चुनौतियों को उजागर किया है, जिससे कांग्रेस को सात में से पांच सीटों पर निर्णायक जीत मिली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस गंभीर मामले पर प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र सहित कर्नाटक के अन्य नेताओं को दिल्ली बुलाया है, जिससे पार्टी में संभावित बड़ी कार्रवाई की अटकलें तेज हो गई हैं। यह घटनाक्रम कर्नाटक की राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव और भाजपा के भीतर अनुशासनहीनता के गहरे सवाल खड़े करता है, जो पार्टी के लिए एक प्रमुख राजनीतिक संकट है।

राज्य विधान परिषद चुनावों में क्रॉस-

वोटिंग के बाद, नितिन नवीन ने विजयेंद्र और पार्टी के अन्य नेताओं को तलब किया। नवीन ने चुनाव में क्रॉस-वोटिंग पर कड़ी आपत्ति जताई है और येदियुरप्पा व अन्य नेताओं से 23 जून को यहां उनसे मुलाकात को कहा है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नयी सरकार के कार्यभार संभालने के बाद हुए पहले चुनावी मुकाबले में, सत्ताधारी कांग्रेस ने विधान परिषद की सात सीट में से पांच पर जीत हासिल की जबकि विपक्षी दल भाजपा ने दो सीट जीतीं।

जनता का पैसा हड़पने वालों की मिलीभगत पर सुप्रीम आदेश

» शीर्ष कोर्ट ने कहा- जांच हो यह धोखाधड़ी मंजूर नहीं
» केंद्र व आरबीआई से मांगा जवाब

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने जिस तरह से स्ट्रेस्ड लोन (फंसे हुए कर्ज) को असाइन और सेटल किया जा रहा था, उस पर चिंता जताई है।

उन्होंने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी), कर्ज लेने वालों और बैंकों के बीच कथित मिलीभगत से जनता के हजारों करोड़ रुपये की हेराफेरी के मामले में कहा, एआरसी, बैंक और कर्ज लेने वाले के बीच एक गहरी मिलीभगत है।' सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के गृह और वित्त मंत्रालयों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से जवाब मांगा है। यह मामला नोएडा की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से जुड़े घोटाले से संबंधित है।

सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने 4 हफ्ते में मांगा जवाब

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहन की वेकेशन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई), एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी), सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ), सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) से चार हफ्ते के अंदर जवाब मांगा।

सीजेआई सूर्यकांत बोले, बिना सोचे-समझे कर्ज क्यों बांटते हैं

लाइव लॉ की रिपोर्ट में कहा गया है कि याचिकाकर्ता का कहना था कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों का 1,537 करोड़ रुपये का कर्ज दो एआरसी के जरिए सिर्फ 73.5 करोड़ रुपये में निपटा दिया गया, जिससे जनता के पैसे का भारी नुकसान हुआ। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा एआरसी, बैंक और कर्ज लेने वाले के बीच एक गहरी मिलीभगत है। चीफ जस्टिस ने आगे कहा, 'लेकिन यह कैसी व्यावसायिक समझदारी है कि आप टैक्स देने वालों का पैसा यानी जनता का पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर उसे बिना सोचे-समझे कर्ज के तौर पर बांट देते हैं। और बाद में उसे वसूलने की कोई कोशिश नहीं करते? इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है।'

कांग्रेस का एनडीए सरकार पर प्रहार

राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे पीएम मोदी को घेरा, बोले- जनता महंगाई से त्रस्त, भाजपा नेताओं की खरीद-फरोख्त में व्यस्त

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को नरेन्द्र मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन का आरोप लगाया और दावा किया कि जब देश के लोगों किए रोजमर्रा का खर्च उठाना मुश्किल होता जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दूसरे दलों के नेताओं की खरीद-फरोख्त में लगी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर देश की अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन का गंभीर आरोप लगाया है।

खरगे ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब देश की आम जनता के लिए अपनी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों का खर्च उठाना भी मुश्किल होता जा रहा है, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अन्य दलों के नेताओं की खरीद-फरोख्त (हॉर्स-ट्रेडिंग) में व्यस्त है। कांग्रेस अध्यक्ष का यह बयान तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और शिवसेना (यूबिटी) में हुई हालिया सियासी बगावत और राजनीतिक उथल-पुथल की पृष्ठभूमि में आया है। खरगे ने तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उबाठा) में हुयी बगावत की पृष्ठभूमि में यह आरोप लगाया। खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, बेतहाशा महंगाई के कारण लोगों की बचत तेजी से खत्म हो रही है। बढ़ती महंगाई, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, असमानता और युवाओं में बढ़ता असंतोष मोदी सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन का परिणाम है।

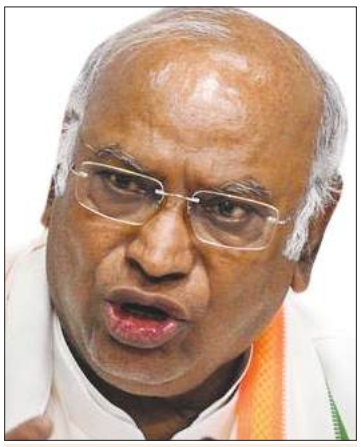

विपक्ष को तोड़ने में लगी भाजपा

अंत में खरगे ने भाजपा की राजनीतिक कार्यशैली पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि एक तरफ देश का आम नागरिक बुनियादी खर्चों के लिए संघर्ष कर रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने और उनके नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए राजनीतिक जोड़-तोड़ और खरीद-फरोख्त में अपनी पूरी ताकत लगा रहा है।

डीएमके के साथ मिलकर लड़ते रहेंगे

अपने 56वें जन्मदिन पर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के ज़रिए एक अहम राजनीतिक साझेदारी को जारी रखने का संकेत दिया। उन्होंने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का शुक्रिया अदा किया और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए उनके साझा संकल्प पर ज़ोर दिया। एक्स पर अपनी पोस्ट में, गांधी ने गठबंधन को भरोसा दिलाते हुए लिखा आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, थिरु एम.के. स्टालिन। भारत की सोच, हमारे संविधान और संघवाद की रक्षा करने का हमारा साझा संकल्प हमें आगे भी राह दिखाता रहेगा - यह हमारी लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की लड़ाई है, और हम जीत मिलने तक मिलकर लड़ते रहेंगे।

चिकित्सा संबंधी महंगाई 15 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है

उन्होंने दावा किया कि खुदरा महंगाई 16 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है, खाद्य महंगाई दर 4.78 प्रतिशत है और चिकित्सा संबंधी महंगाई 15 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में गिरावट आ रही है, विदेशी निवेशक भारत से दूरी बना रहे हैं तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं होने से बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया, एक ओर आम आदमी के लिए बुनियादी जरूरतों का खर्च उठाना मुश्किल होता जा रहा है, वहीं भाजपा अन्य दलों के नेताओं को अपने साथ लेने के लिए खरीद-फरोख्त में व्यस्त है।

प्रियांक खरगे के सपोर्ट में उतरी सीपीआई

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे के समर्थन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) खुलकर सामने आ गई है। सीपीआई महासचिव डी. राजा ने बीजेपी सांसद रमेश जिगाजिनगी के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि संविधान की ताकत के साथ वे आरएसएस-बीजेपी से सवाल पूछते रहेंगे और जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। डी. राजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी सांसद रमेश जिगाजिनगी के बयान को जातिवादी मानसिकता का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां यह दर्शाती हैं कि आरएसएस-बीजेपी के भीतर दलित समुदायों के प्रति गहरा पूर्वाग्रह मौजूद है. उन्होंने कहा कि ऐसे बयान समानता नहीं, बल्कि सामाजिक ऊंच-नीच और जातिगत पदानुक्रम वाली सोच को बढ़ावा देते हैं। सीपीआई नेता ने कहा कि आरएसएस-बीजेपी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें दलितों द्वारा अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करने और सवाल पूछने से परेशानी क्यों होती है. डी. राजा ने कहा, डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान की ताकत के साथ हम आरएसएस-बीजेपी से सवाल पूछते रहेंगे और जाति व्यवस्था के खात्मे के लिए संघर्ष जारी रखेंगे उन्होंने कहा कि समानता, सम्मान और न्याय के लिए लड़ने वाली लोकतांत्रिक आवाजों को कोई भी धमकी चुप नहीं करा सकती।

खान सर को सिविल कोर्ट से बड़ी राहत

» अंतरिम सुरक्षा रहेगी जारी 25 जून को अगली सुनवाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। प्रसिद्ध शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को जमानत मामले में फिलहाल राहत मिली हुई है। शनिवार (20 जून) को पटना सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पुलिस ने केस डायरी कोर्ट में जमा कर दी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने खान सर को मिली अंतरिम सुरक्षा (इंटरिम प्रोटेक्शन) को अगली तारीख तक बढ़ा दिया है। अब 25 जून तक उनके खिलाफ किसी तरह की गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक खान सर को अंतरिम राहत जारी रहेगी। इसके साथ ही उनके पक्ष से जुड़े अन्य लोगों को भी राहत दी गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ फिलहाल कोई बलपूर्वक या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी पुलिस किसी भी तरह की दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं कर सकेगी। खान सर के साथ जुड़े तीन स्टाफ सदस्य, जिनकी तलाश पुलिस कर रही थी, उन्हें भी अदालत से राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ भी फिलहाल कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। इससे खान सर के पक्ष को बड़ी राहत मिली है।

इज़राइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर के बयान पर भारत में मचा घमासान

» कांग्रेस ने एनडीए सरकार पर दागा सवाल
» पीएम मोदी चुप्पी देश के लिए नुकसानदायक : जयराम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। अमेरिका-ईरान समझौते का दुनिया भर में सावधानी के साथ स्वागत किया गया है, कई खतरों का सामना भी करना पड़ रहा है। इनमें सबसे बड़ा खतरा इज़राइल से है। इज़राइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर जैसे ऊँचे पद पर बैठे व्यक्ति ने अभी-अभी पूरे लेबनान को जलाकर राख करने की बात कही है। इसको लेकर भारत में भी सवाल उठ रहे है। कांग्रेस ने इसम मामले में मोदी सरकार पर हमला किया।

सीनियर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को भारत की चुप्पी पर सवाल उठाए। यह चुप्पी तब देखी गई जब एक इज़राइली मंत्री ने पूरे लेबनान को जलाकर राख करने की धमकी दी। रमेश ने कहा कि इससे देश के हितों को नुकसान पहुँचता है। एक्स पर एक तीखी पोस्ट में उन्होंने कहा कि जहाँ दुनिया भर में ईरान-अमेरिका शांति समझौते का सावधानी के साथ स्वागत किया गया है, वहीं सीनियर इज़राइली नेता के बयानों से शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। अमेरिका-ईरान एमओयू, जिसका दुनिया भर में सावधानी के साथ स्वागत किया गया है, को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें सबसे बड़ा खतरा इज़राइल से है। इज़राइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर जैसे ऊँचे पद पर बैठे व्यक्ति ने अभी-अभी पूरे लेबनान को जलाकर राख करने की बात कही है। उन्होंने भारत और केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा, लेकिन हमेशा की तरह, मोदी सरकार पूरी तरह चुप है।

सरयू की कोख से सुनहरे रेत का कारोबार

गांजर की सियासी पिच पर फर्राटा भर रहे खनन माफिया, पुलिस भी कार्रवाई से कतराती

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क/वली चौधरी

सीतापुर। श्रमिकों और जेसीबी के सहारे गांजर में चमकती बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। पुलिस के टोटकों में कैरियर हैं लेकिन खनन विभाग फिलहाल कागजी कार्यवाही तक सीमित है। लिहाजा विभागीय अभयदान से राजस्व चोरी का ग्राफ भी बढ़ चला है। जिले की महमूदाबाद तहसील के सबसे अधिक बाढ़ और कटान प्रभावित रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में बहने वाली गोबरहिया नदी इन दिनों अवैध खनन माफियाओं के निशाने पर है।

गर्मी के मौसम में नदी का जलस्तर कम होते ही संगठित तरीके से बालू और मिट्टी की खुदाई शुरू हो जाती है। इलाका वासियों की मानें तो, नदी की कछारों पर रातभर जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टर-ट्रालियों की आवाजाही देखी जा सकती है। हर रोज सैकड़ों ट्रॉली बालू और मिट्टी निकाली जा रही है। इलाके के दुर्गेश, बल्लू, अमित, केसरी लाल, मोहित आदि का दावा है कि अवैध रूप से निकाली गई बालू 3000 से 4000 रुपये प्रति ट्रॉली तक जनपद ही नही सरहद पार बाराबंकी समेत अन्य इलाकों में बेंची जा रही है। इससे सरकार को मिलने वाले राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। गांजरवासी बताते हैं कि पड़ोसी जनपद बाराबंकी में घाघरा नदी से खनन के लिए निर्धारित प्रक्रिया और रॉयल्टी व्यवस्था लागू है, जबकि यहां अवैध खनन का कारोबार खुलेआम चल रहा है। गोबरहिया नदी की कछार सिंडिकेट का हब बनी है। इन दिनों यहां बड़े पैमाने पर बालू खनन किए जाने की चर्चा है। शुकुलपुरवा, धान्धी, सोहरिया, कनरखी और केवड़ा समेत कई गांवों के लोगों का कहना है कि खनन माफियाओं की दबंगई के चलते कोई खुलकर विरोध नहीं कर पाता। बाशिंदों का दावा है कि विरोध करने वालों को अंजाम भुगतने की हिदायत शातिरों द्वारा दी जाती है। लगातार गहरी खुदाई के कारण कई स्थानों पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जो बरसात के दौरान नाले का रूप लेकर हादसों की वजह भी बन सकते हैं। उधर, जिला खनन अधिकारी शालिनी कुमारी ने बताया कि अवैध खनन की गतिविधियों की लगातार निगरानी की जा रही है। मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा उच्चाधिकारियों को भी नियमित रूप से जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

गोबरहिया नदी क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें संज्ञान में हैं। विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। यदि कहीं बिना अनुमति बालू या मिट्टी का खनन पाया जाता है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त सूचनाओं और तथ्यों की जांच कराई जा रही है। - **शालिनी कुमारी**, जिला खनन अधिकारी

महाराष्ट्र कार्यालय:- 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क, 2-डी सिटी मॉल, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400053। **विधि सलाहकार**: मोहम्मद हैदर
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
RNI-UPHIN/2015/62233, **दूरभाष**: 0522- 4078371 | **Email**: daily4pm@gmail.com | **website**: www.4pm.co.in |
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।

स्वामी **4 पीएम** न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक एवं प्रकाशक **संजय शर्मा**
द्वारा **आस्था प्रिंटर्स**, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित
पता 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। **संपादक- संजय शर्मा**